दिवालिया परिसंपत्तियों को मिलेगी कर राहत!

दिलाशा सेठ और इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 18 दिसंबर

सरकार इनसॉल्वेंसी (दिवालिया प्रक्रिया) के तहत खरीदी गई परिसंपत्तियों के लिए कर राहत देने पर विचार कर रही है। इनमें कर छूट जैसी सुविधाएं बजट में दी जा सकती हैं। सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संदर्भ में राहत दिए जाने के लिए जीएसटी परिषद से संपर्क कर सकती है।

सूत्रों का कहना है कि स्टांप शुल्क पर कर राहत के लिए राज्यों के सहयोग की जरूरत होगी। इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों को कर संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है जिससे समाधान प्रक्रिया जटिल हो गई है।

कंपनियों को परिसंपत्तियों के साथ साथ ब्रांड की बिक्री पर जीएसटी का सामना करना पड़ता है। इससे पहले सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज (स्पेशल प्रोवीजंस) ऐक्ट के तहत कंपनियों को केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से छूट प्राप्त थी। जीएसटी के शुरू होने से सीएसटी उपयोगी नहीं रह गया है।

जीएसटी से छूट से कंपनियों को ऊंची कीमतों पर परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने और कर्जदाताओं को अधिक रकम देने में मदद मिलेगी।

डेलॉयट इंडिया के अमरीश शाह का कहना है, 'यदि जीएसटी छूट इनसॉल्वेंसी एंड बैंगक्रप्सी कोड (आईबीसी) प्रक्रिया के अधीन बेची गई संपत्तियों के लिए दी जाती है तो इससे ऋणदाताओं के लिए वसूली तेज करने में मदद मिलेगी।'

इसी तरह भूमि समेत परिसंपत्तियों की बिक्री पर स्टांप शुल्क लगेगा। स्टांप शुल्क विभिन्न राज्यों से 3-10 के दायरे में अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में यह 5 फीसदी के आसपास है।

स्टांप शुल्क राज्य के अधीन है और इसमें राज्यवार ढंग से संशोधन किए जाने की जरूरत है। भले ही केंद्रीय कानून 'इंडियन स्टांप ऐक्ट, 1989' मौजूद है, लेकिन दरों का निर्धारण राज्यों द्वारा ही किया जाता है। दरअसल, राज्यों को अधिनियम में किसी तरह का बदलाव करने और इस संबंध में अपने स्वयं के नियम बनाने का अधिकार हासिल है।

किसी खास राज्य में भी ये एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में बॉम्बे स्टांप ऐक्ट, 1958 है जो स्टांप शुल्क से जुड़े मामले देखता है। वहीं गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में अपने स्वयं के स्टांप शुल्क कानून हैं। इसके अलावा खरीदी गई कंपनी के नुकसान कर कर छूट को उस कंपनी को स्थानांतरित करना भी एक बड़ी समस्या है जिसने इसे खरीदा हो।

मौजूदा कानूनों के अनुसार दिवालियापन की प्रक्रिया से जुड़ी कंपनी को मिलने वाली कर छूट को बरकरार नहीं रखा जा सकता, जिससे संभावित खरीदारों के लिए इनका अधिग्रहण करना आकर्षक नहीं रह गया है।

शाह ने कहा, 'कर के नजरिये से आईबीसी प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने के लिए आईबीसी के तहत किसी कंपनी के आगे के नुकसान को अधिग्रहीत कंपनी को स्थानांतरित किया जाएगा।'

डेलॉयट की नीरू आहूजा का कहना है, 'आईबीसी के तहत शामिल कंपनियों के लिए कर समस्याओं से भविष्य में बड़ी तादाद में कर विवादों को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए यह सरकार को जल्द से जल्द इसका समाधान निकालने की जरूरत है।'

कंपनी मामलों के मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में सरकार द्वारा हाल में बनाई गई समिति इन बदलावों पर विचार कर रही है।

कर बोझ को कम करने की तैयारी

- कर राहत के लिए सरकार जीएसटी परिषद से कर सकती हैं संपर्क
- सरकार द्वारा हाल में बनाई गई समिति इन बदलावों पर कर रही है विचार

खरीदार दिखने से ऑर्किड फार्मा के शेयर में तेजी

गिरीश बाबू
चेन्नई, 18 दिसंबर

- कई कंपनियों ने दिखाई है अधिग्रहण में दिलचस्पी
- कंपनी पर बैंकों के एक कंसोर्टियम का 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण बाकी है

इन खबरों के बाद सोमवार को ऑर्किड फार्मा का शेयर 5 प्रतिशत चढ़ गया कि कुछ दवा कंपनियां कर्ज से लदी इस कंपनी को खरीदने की संभावना तलाश रही हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि जहां चेन्नई की इस कंपनी को खरीदने के लिए कंपनियों में होड़ इसकी विनिर्माण इकाइयों को अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफडीए) द्वारा मंजूरी मिलने की वजह से देखी जा रही है वहीं इसके लिए बैंकों के एक कंसोर्टियम का ऋण 3,000 करोड़ रुपये के पार जा चुका है। ऐसी खबरें आई थीं कि अरविंदो फार्मा और डॉ. रेड्डीज इस कंपनी को खरीदने की संभावना तलाश रही हैं। ऑर्किड फार्मा 17 अगस्त 2017 से कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत है। जहां अरविंदो ने इस तरह की खबर से इनकार कर दिया है वहीं डॉ. रेड्डीज ने कहा है कि वह अफवाह या अटकलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती।

कंपनी का शेयर पिछले बंद स्तर 17.80 की तुलना में 18.65 रुपये पर खुला और इसमें 4.78 फीसदी की तेजी दर्ज की गई और यह पूरे दिन इसी दायरे में बना रहा।

इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के अनुसार इच्छुक पक्ष रिजोल्यूशन प्लान सौंपेंगे जिसमें कर्ज अदायगी और अन्य पहलू शामिल होंगे। ईओआई को नॉन-बाइंडिंग बिड और फिर बाइंडिंग बिड में तब्दील किया जाएगा।

विश्लेषकों का कहना है कि ऑर्किड फार्मा के प्रति दवा कंपनियों का आकर्षण तमिलनाडु में इसकी यूएसएफडीए स्वीकृत इकाई की क्षमता वृद्धि की वजह से दिखा है। एक विश्लेषक ने कहा कहा कि एब्रेविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस (एएनडीए) और इकाइयां भी खरीदार के लिए आकर्षण की वजह हो सकती हैं, लेकिन उसे देनदारियों पर भी विचार करने की जरूरत होगी। एक अन्य विश्लेषक ने कहा, 'कंपनी के संयंत्रों को लेकर फिलहाल कोई समस्या नहीं है। चूंकि विक्रेता वित्तीय संकट की स्थिति में है, इसलिए उसकी परिसंपत्तियां उन अन्य कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी जो विलय एवं अधिग्रहण के जरिये विस्तार की संभावना तलाश रही हैं।' हालांकि सेफलोस्पोरिन एपीआई के लिए मार्जिन आकर्षक नहीं होगा, लेकिन कंपनियों की नजर फॉर्मूलेशन व्यवसाय पर बनी रहेगी। अमेरिका में फॉर्मूलेशन उपस्थिति वाली कंपनियां अपनी बाजार बढ़ाने की रणनीति के तहत इसका इस्तेमाल कर सकेंगी।

स्टरलाइट को ब्राजील में परियोजना मिली

श्रेया जय
नई दिल्ली, 18 दिसंबर

अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाते हुए स्टरलाइट पावर ने ब्राजील में सबसे बड़ी विद्युत पारेषण परियोजनाओं में से एक को अपनी झोली में डाल लिया है। यह परियोजना 80 करोड़ डॉलर की है और देश में कंपनी द्वारा हासिल की गई यह तीसरी परियोजना है।

ब्राजील ने रिवर्स नीलामी निविदा के जरिये 1800 किलोमीटर की इस ट्रांसमिशन परियोजना जारी की। इसे हासिल करने की दौड़ में अन्य कंपनियां थीं स्टेट ग्रिड ऑफ चाइना, एंजी इलेकनोर और भारतीय कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ब्राजील द्वारा अब तक नीलामी के लिए पेश की गईं सभी 11 परियोजनाओं की क्षमता में इस परियोजना का योगदान 40 फीसदी से अधिक का है।

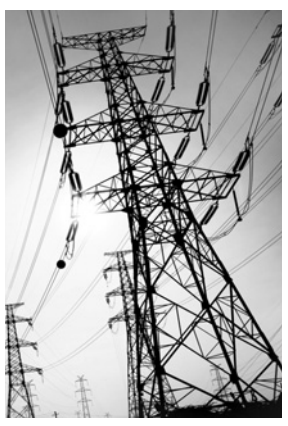

- पावरग्रिड, स्टेट ग्रिड ऑफ चाइना को पीछे छोड़कर हासिल की परियोजना

इस परियोजना के साथ ब्राजील में स्टरलाइट का निवेश 1 अरब डॉलर को पार कर गया है, जो लैटिन अमेरिका में किसी भारतीय कंपनी द्वारा सर्वाधिक निवेश है। कंपनी ने अप्रैल 2017 में दो विद्युत पारेषण परियोजनाएं हासिल की थीं।

स्टरलाइट पावर के मुख्य कार्याधिकारी प्रतीक अग्रवाल ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'ब्राजील के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है और हमने इसे कोई बहुत बड़ी और आक्रामक बोली के जरिये हासिल नहीं किया है।' ब्राजीलियाई व्यवसाय के बारे में विस्तार से बताते हुए अग्रवाल ने कहा कि वे भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की तरह ही ऋण-पूंजी अनुपात के तहत स्थानीय तौर पर पूंजी जुटाएंगे।

विदेशी निवेश का बड़ा हिस्सा आया भारत

पवन बुरुगुला
मुंबई, 18 दिसंबर

भारत ने दो साल के अंतराल के बाद वर्ष 2017 में उभरते बाजारों (ईएम) में विदेशी प्रवाह का बड़ा हिस्सा आकर्षित किया। पिछले दो वर्षों में घरेलू बाजारों में दक्षिण कोरिया और ताइवान की तुलना में दबाव देखा गया क्योंकि ये बाजार बेहतर आय वृद्धि दर्ज करने में कामयाब रहे थे।

आय और आर्थिक परिदृश्य में सुधार इस साल भारतीय इक्विटी के पक्ष में बना हुआ है। प्राथमिक बाजार में बड़े आकार के निर्गमों से भारत को अच्छी वैश्विक पूंजी आकर्षित करने में मदद मिली है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार विदेशी फंडों ने भारतीय बाजारों से 8.2 अरब डॉलर की कुल खरीदारी की जो सभी प्रमुख उभरते बाजारों द्वारा प्राप्त निवेश का लगभग 50 प्रतिशत है। उभरते बाजारों के संयुक्त निवेश में चीन और रूस को अलग रखा गया है क्योंकि इन दो देशों के लिए आंकड़ा अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रवाह की प्रतिशतता के संदर्भ में 2017 के लिए निवेश भागीदारी में भारत का हिस्सा पांच साल में सर्वाधिक है।

विदेशी फंडों से मजबूत प्रवाह के साथ साथ घरेलू म्युचुअल फंडों द्वारा अच्छी खरीदारी से भी भारतीय बाजारों को 2017 के दौरान नई ऊंचाई पर पहुंचने में मदद मिली। सेंसेक्स वर्ष 2017 के दौरान डॉलर के संदर्भ में 34 फीसदी चढ़कर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वैश्विक बाजारों में शुमार हो गया। विश्लेषकों का मानना है कि भारत विदेशी प्रवाह के संदर्भ में रफ्तार बनाए रख सकता है। ऐसे कई कारक हैं जिनसे अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की राह पर लौटने में सक्षम है। कॉरपोरेट आय अगले दो वित्त वर्षों के लिए दो अंक में रहने का अनुमान है। आईपीओ और कोष उगाही के अन्य विकल्पों में मजबूती आने से भी विदेशी प्रवाह आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

नोमुरा के प्रबंध निदेशक रॉबर्ट सुब्बारमन का कहना है, 'भारत उभरते बाजारों में हमारा नंबर वन पसंदीदा देश है। यहां चक्रीय और संरचनात्मक सुधार दर्ज किया गया है। मेरा मानना है कि अगले साल बाजार में तेजी शुरू हो जाएगी। साथ ही हमारा मानना है कि यह एक बेहद परिपक्व अर्थव्यवस्था है, जहां मजबूत और टिकाऊ वृद्धि दर्ज की जा सकती है।' नोमुरा समेत गोल्डमैन सैक्स और क्रेडिट सुइस जैसी अन्य विदेशी ब्रोकरेज फर्मों को अगले साल भारतीय इक्विटी में 10-15 फीसदी वृद्धि की उम्मीद है।

आईपीओ के संदर्भ में 11 अरब डॉलर से अधिक के निर्गमों के साथ वर्ष 2017 श्रेष्ठ वर्ष रहा है। 2018 के लिए नए निर्गमों का अनुमान 8-10 अरब डॉलर के दायरे में है।

क्रेडिट सुइस में इंडिया इक्विटी रणनीतिकार नीलकंठ मिश्रा का कहना है, 'नवंबर में मजबूत एफआईआई प्रवाह खासकर बड़े बीमा आईपीओ की वजह से दर्ज किया गया। हमें विश्वास है कि ऐसी कई और बड़ी कंपनियां अगले साल भी आईपीओ लाएंगी। इससे रणनीतिक निवेशकों को इनमें भागीदार बनने का अवसर मिलेगा।'

वैश्विक तरलता उभरते बाजारों के लिए निवेश प्रवाह बनाए रखने के संदर्भ में एक अन्य प्रमुख पहलू है। कई विश्लेषकों का कहना है कि कम से कम 2018 की पहली छमाही में विदेशी निवेश प्रवाह मजबूत बना रहेगा।

ईबीबी और प्रवाह

भारत एफआईआई से अच्छा निवेश हासिल करने में सफल रहा है

एफआईआई प्रवाह ($ bn)	2013	2014	2015	2016	2017
भारत	19.6	16.2	3.3	2.9	8.2
ताइवान	9.2	13.2	3.4	11.0	6.0
दक्षिण कोरिया	4.9	5.7	-3.6	10.5	8.1
इंडोनेशिया	-1.8	3.8	-1.6	1.3	-2.9
दक्षिण अफ्रीका	0.1	1.5	0.7	-8.6	-3.9
ब्राजील	4.9	9.0	5.7	3.9	3.0
कुल	**36.8**	**49.3**	**7.9**	**20.9**	**18.4**
भारत की भागीदारी (%)	**53.2**	**32.8**	**41.4**	**13.9**	**44.5**

स्रोतः ब्रोकरेज रिपोर्ट

सुधरते आर्थिक और आय परिदृश्य, प्राथमिक बाजार में तेजी से भारत को अगले साल मजबूत बने रहने में मदद मिलेगी

देना बैंक
DENA BANK
(भारत सरकार का उद्यम)
विश्व स्त पारिवारिक बैंक

प्रोजेक्ट कार्यालय, आईटी विभाग, पटेल ईस्टेट, एमटीएनएल बिल्डींग के पास, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई- 400102

देना बैंक प्रस्ताव के लिए अनुरोध कर रहा हैं गिफ्ट सिटी गाँधीनगर, गुजरात में आईटी और संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर (लैन केबलिंग, ईपीबीएक्स, यूपीएस, डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्कैनर्स, ऑडियो विजुअल सिस्टम) की स्थापना (निविदा: एचओ/आईटीडी/859/2017 दिनांक-18/12/2017).

देना है तो भरोसा है

बीएस बातचीत

'भाजपा की जीत सकारात्मक'

गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव नतीजे उम्मीद के अनुरूप रहे हैं। यूबीएस सिक्योरिटीज में भारतीय शोध के प्रमुख **गौतम छाछड़िया** ने **पुनीत वाधवा** के साथ बातचीत में कहा कि चुनावी परिणाम के बाद बाजारों की नजर फिर से कॉरपोरेट आय, सुधार और वैश्विक घटनाक्रम पर लगी रहेगी। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंशः

आप गुजरात के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
हम पहले से ही भाजपा की जीत की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि पिछले कुछ सप्ताहों से चिंताएं बरकरार थीं। इससे निवेशकों के बीच बिकवाली को बढ़ावा मिला। सोमवार के चुनावी नतीजे भी एक्जिट पोल के अनुरूप रहे हैं। बाजार में कुछ दिन तक चुनावी परिणाम का असर बरकरार रहेगा और फिर यह अन्य कारकों पर केंद्रित हो जाएगा।

अगले कुछ महीनों के दौरान बाजार को गति कैसे मिलेगी?
जनवरी के आय सीजन, केंद्रीय बजट और वैश्विक घटनाक्रम से बाजार को गति मिलेगी। इसके अलावा बाजार की नजर अन्य वृहद आर्थिक आंकड़ों, खासकर मुद्रास्फीति पर लगी रहेगी। जब चुनाव परिणाम के बाद पैदा हुआ उत्साह धीमा पड़ जाएगा तो अन्य कारक बाजार पर हावी होने लगेंगे।

आपको सरकार के शेष कार्यकाल से क्या उम्मीदें हैं?
हम अब आम चुनाव के नजदीक हैं। ये चुनाव मई 2019 में प्रस्तावित हैं। मैं नहीं मानता कि सरकार सुधारों पर सख्ती दिखाएगी। सरकार एयर इंडिया के निजीकरण पर ध्यान देने की कोशिश करेगी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण को मजबूती प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण को लेकर बाजार किस तरह की स्पष्टता चाहता है?
इस बारे में योजना का खुलासा जनवरी या इससे पहले भी किया जा सकता है। किसी तरह की मंजूरी या अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनावों का इंतजार कर रही थी। पहला कदम पूंजी की पहली किस्त की घोषणा करना होगा। दूसरे हिस्से में खास पीएसबी के लिए कई अन्य सुधारों को शामिल किया जा सकता है। मैं नहीं मानता कि बैंकों के शेयरों में तेजी का सिलसिला पूरा हो चुका है। यदि पुनर्पूंजीकरण और गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) का समाधान चक्र तय योजना के अनुसार बरकरार रहा तो बैंक शेयरों में और तेजी आ सकती है।

क्या आप मानते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद विदेशी निवेश भारत में लौटेगा?
विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भारत पर 'ओवरवेट' बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने भारत को लेकर अपने नजरिये में थोड़ा बदलाव भी किया है, क्योंकि अन्य उभरते बाजारों ने प्रतिफल देना शुरू कर दिया है। क्या एफआईआई निवेश भारत आएगा या नहीं या क्या वे भारत के लिए अपना निवेश आवंटन बढ़ाएंगे या नहीं, यह मौजूदा समय में कहना मुश्किल है। स्थिति काफी हद तक इस पर निर्भर करेगी कि आय की रफ्तार कैसी रहती है।

क्या आपको वित्त वर्ष 2018 के शेष समय और वित्त वर्ष 2019 में कॉरपोरेट आय में तेजी की उम्मीद दिख रही है?
वित्त वर्ष 2018 लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन हमें कुछ बदलावों की उम्मीद दिख रही है। आय के आंकड़ों पर उन बैंकों का असर बना रहेगा जो अधिक प्रावधान की वजह से प्रभावित हुए हैं। मेरा मानना है कि अगले साल प्रावधान में कमी आएगी, भले ही प्रमुख आर्थिक गतिविधि धीमी बनी रहेगी।

JK Cement LTD.

CIN:L17229UP1994PLC017199
Registered and Corporate Office:
Kamla Tower, Kanpur-208001, Uttar Pradesh, India
Telephone: +91 512 2371478/81, Fax: +91 512 2399854
Email: shambhu.singh@jkcement.com Web: www.jkcement.com

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS/ MEMBERS
Transfer of Shares to the Investor Education and Protection Fund

Members are hereby informed that in terms of Section 124 of the Companies Act, 2013, notified by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (MCA), Equity Shares of the Company in respect of which dividend entitlements have remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more, are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) of the Government of India.

Unclaimed or unpaid dividend up to the year ended 31st March, 2010 has been transferred by the Company to the IEPF within the statutory time period and such dividend from the year ended 31st March, 2011 is presently lying with the Company.

In terms of the IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('the said Rules') the concerned Members are being provided an opportunity to claim such dividend for the year ended 31st March, 2011 and onwards by sending a letter under their signature so as to reach the Kamla Tower, Kanpur - 208001, Uttar Pradesh,India by Saturday 20th January, 2018. The details of the concerned Members and the shares for transfer to the IEPF are available on the Company's corporate website at the link http://www.jkcement.com/ under the section 'Information about IEPF'. In the event valid claim is not received by Company by that date, the Company shall take action towards transfer of the shares to the IEPF, as stated above, on Wednesday, 31st January, 2018 pursuant to the said Rules. Once these shares are transferred to the IEPF by the Company, such shares may be claimed by the concerned Members only from the IEPF Authority by following the procedure prescribed in the said Rules.

Individual letters in this regard have been sent to the concerned Members at their address registered with the Company. Clarification in this matter, if required, may be sought from Company by sending email at shambhu.singh@jkcement.com/rc.srivastava@jkcement.com or by calling Share Department at telephone nos. 0091-512-2371478/81 Extension Nos. 18322/323.

This notice is published pursuant to the provisions of the IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

By Order of the Board

Place : Kanpur (Shambhu Singh)
Date : 19th December, 2017 Asst. Vice President (Legal) & Company Secretary

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK
विश्वास की परंपरा A tradition of trust

प्रधान कार्यालय : 2 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001

असाधारण आम सभा एवं ई-वोटिंग की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा बुधवार, 17 जनवरी, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन ऑडीटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 में निम्नांकित व्यवसाय के निमित्त आयोजित की जाएगी :

''कर्मचारी शेयर क्रय योजना (''आलबैंक-ईएसपीएस'') के अंतर्गत ऐसी कीमत अथवा कीमतों पर बोर्ड/समिति द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार यथानिर्णीत निबंधनों और शर्तों पर लाभांश के भुगतान सहित समस्त प्रयोजनों और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों की सममात्रा रैंकिंग के साथ ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5,00,00,000 (पांच करोड़) तक के नए इक्विटी शेयरों का एक अथवा अधिक चरणों में सृजन, प्रदान, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करने हेतु।''

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : कोलकाता (उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन)
तारीख : 12.12.2017 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियां :

1. **नोटिस का प्रेषण :**
बैंक की असाधारण आम सभा (ईजीएम) के आयोजन की व्यक्तिगत सूचना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र एवं प्राक्सी फार्म संलग्नित है, बैंक के सभी शेयरधारकों को डाक से/ई-मेल पर भेजी जा चुकी है।
जिन शेयरधारकों को नोटिस प्राप्त नहीं होता, वे अपनी शेयरधारिता का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत कर नोटिस की डुप्लीकेट प्रति कंपनी सचिव, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, इलाहाबाद बैंक प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता 700001 से प्राप्त कर सकते हैं। नोटिस बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर भी प्रदर्शित है।
2. **इलेक्ट्रानिक माध्यमों से वोटिंग :**
शेयरधारक कृपया नोट करें कि स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता करार एवं सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में बैंक नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लि. (एनएसडीएल) के माध्यम से व्यवसाय मद के संचालन हेतु रिमोट ई-वोटिंग (इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली का प्रयोग करते हुए असाधारण आम सभा स्थल से इतर किसी अन्य स्थान से वोट डालना) सुविधा प्रदान कर रहा है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 14 जनवरी, 2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से आरंभ होकर मंगलवार, 16 जनवरी, 2018 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा उसके बाद डिसेबल कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
3. बैंक ने बैठक की कार्यसूची मद पर वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग एवं मतदान) में सहभागिता हेतु पात्र शेयरधारकों के मताधिकार के निर्धारण हेतु **नियत तिथि बुधवार, 10 जनवरी, 2018 को** निर्धारित किया है। केवल वही व्यक्ति जो निर्धारित नियत तिथि को शेयरधारक है, वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा ईजीएम स्थल पर होने वाले मतदान के माध्यम से बैठक की कार्यसूची मद पर वोट देने हेतु पात्र होंगे।
4. कोई व्यक्ति जो नोटिस प्रेषित किए जाने के बाद बैंक के शेयर अर्जित करता है/बैंक का शेयरधारक बनता है और नियत तिथि अर्थात 10 जनवरी, 2018 को बैंक के शेयर धारण करता है, तो वह evoting@nsdl.co.in अथवा rta@cbmsl.com/ investors.grievance@allahabadbank.in पर अपना अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
5. कोई व्यक्ति जिसका नाम शेयरधारकों के रजिस्टर में अभिलिखित है अथवा नियत तिथि को डिपाजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थ स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग अथवा मतदान के माध्यम से असाधारण आम सभा स्थल में वोटिंग सुविधा पाने का हकदार है।
6. रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प लेने वाले शेयरधारक सभा में भाग लेने के हकदार होंगे, किंतु, असाधारण आम सभा स्थल पर मत डालने के हकदार नहीं होंगे।
7. रिमोट ई-वोटिंग तथा असाधारण आम सभा स्थल पर मतदान का सकल परिणाम बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा तथा इसकी सूचना असाधारण आम सभा के बाद नियत समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।
8. किसी प्रकार की शंका के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा एनएसडीएल को टोल फ्री नं. 1800 222990 पर संपर्क कर सकते हैं। शेयरधारक, कंपनी सचिव, इलाहाबाद बैंक से 033-22420878 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा अपनी शंकाएं investors.grievance@allahabadbank.in पर ई-मेल कर सकते हैं।